पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलावार को भारी जनसमूह के समर्थन के साथ टोंक विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पायलट के साथ चल रहे व्यापार मंडल के सदस्य, कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जन काफी उत्साहित नज़र आये। सबसे पहले पायलट ने टोंक उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय पहुँचकर लोगों का अभिवादन किया। व्यापार मंडल के सदस्यों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों ने पायलट को मालायें पहनाईं और शुभकामनायें दीं।

महाराष्ट्र में आरक्षण आंदोलन और तेज हुआ

कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए, पांच जिलों में बस व इंटरनैट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा

- **महाराष्ट्र के मु.मंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बयान जारी कर मराठा आंदोलन के एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिला को आश्वस्त करने का प्रयास किया है कि, सरकार मराठा आरक्षण के पूर्णतः पक्ष में है।**

मुंबई, 31 अक्टूबर। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग तेज होती जा रही है। हालात को देखते हुए प्रदेश के पांच जिलो में बस सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्यपाल रमेश बैंस से मुलाकात की और उन्हें हालात से अवगत करा। वहीं, प्रदेश में हिंसा को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मराठा कोटा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल को भी आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार मराठा समुदाय के आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही प्रदेश में शांति के लिए अपील भी की है। इन सबके बीच महाराष्ट्र के धाराशिव और बीड जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

महाराष्ट्र में सोमवार से मराठा आरक्षण की आग और ज्यादा तेज हो गई है। इसको देखते हुए परभानी, धाराशिव, लातूर, जालना और नांदेड़ जिलों में अगले तीन-चार दिनों के लिए बस सेवाएं रोक दी गई हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के बीड जिले में इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। इससे पहले कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम ने महाराष्ट्र के ओमेरगा में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा उनकी एक बस को जलाये जाने के बाद आंदोलन प्रभावित राज्य के लिए अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं।

वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र में मराठा को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया तय करने के लिए नियुक्त उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता वाली समिति की पहली रिपोर्ट मंगलवार को स्वीकार कर ली।

महाराष्ट्र के बेलगाम जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने मंगलवार सुबह करीब छह बजे से तीन दिनों के लिए यहां तीन राज्य मंत्रियों और एक सांसद के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया।

महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) द्वारा बेलगाम जिले और कर्नाटक में मंगलवार सुबह से तीन दिनों के लिए अन्य विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों में ब्लैक-डे आंदोलन चलाया जा रहा है। बेलगावी प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तीन राज्य मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल, दीपक केसरकर, शंभू राज देसाई और हातकनागले लोकसभा क्षेत्र के सांसद धैर्यशील माने को जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए बुधवार के आंदोलन में भाग लेने पर रोक लगा दी है।

एमईएस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हर साल एक नवंबर को कर्नाटक राज्य के स्थापना दिवस पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए काला दिवस मनाया, जिन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के बीच सीमा विवाद पर विरोध प्रदर्शन किया था और महाराष्ट्र राज्य में कर्नाटक राज्य के मराठी भाषी विवादित क्षेत्रों को शामिल करने की मांग की थी।

बेलगाम जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने की संभावना पर यहां के पुलिस अधीक्षक ने जिला कलेक्टर को महाराष्ट्र राज्य के तीन मंत्रियों और एक सांसद पर प्रतिबंध आदेश जारी करने की सिफारिश की। इन मंत्रियों और सांसद के कल आंदोलन में भाग लेने की संभावना है।

टोंक में भारी जनसमूह के साथ पायलट ने नामांकन दाखिल किया

- **पायलट का काफिला भूतेश्वर महादेव से शुरू हुआ और एस.डी.एम. कार्यालय तक पहुंचते पहुंचते तो काफिला भारी जन सैलाब बन गया था।**
- **इस दौरान पुष्कर की प्रत्याशी नसीम अख्तर, मसूदा विधायक राकेश पारीक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।**

टोंक, 31 अक्टूबर। टोंक के पूर्व विधायक सचिन पायलट आज विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस के चिन्ह पर टोंक विधानसभा सीट से अपना नामांकन दर्ज करने पहुंचे।

सुबह 11.30 बजे स्थानीय भूतेश्वर महादेव मन्दिर से रवाना हुई नामांकन रैली में जनसमूह लगातार जुड़ता गया। मुख्य सड़क मार्ग, बड़े कुएं के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, छोटे कामगारों, फूल माला वालों सहित अनेक लोगों ने पायलट को मालाएं व पुष्प भेंट किए। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सचिन पायलट एस.डी.एम. कार्यालय पहुँचे। इससे पहले पायलट ने, टोंक के हदय स्थल घंटाघर चौक पर स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा, पटेल सर्किल पर स्थापित सरदार पटेल की मूर्ति को माल्यार्पण किया।

नामांकन दाखिल करते समय पायलट ने एक फॉर्म में गलती से मोबाइल नम्बर गलत लिख दिया। दस डीजिट नम्बर की जगह नौ नम्बर ही लिखे थे। बाद में एक फॉर्म में त्रुटि में सुधार किया गया। इस फॉर्म के साथ पायलट ने कुल तीन प्रपत्रों में अपना नामांकन उपखण्ड अधिकारी कपिल शर्मा के समक्ष दाखिल किया।

टोंक जिले से पहला नामांकन पत्र सचिन पायलट ने ही दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद पायलट प्रेस से भी मिले और बहुत सौहाद्रपूर्ण वातावरण में पायलट ने कहा कि, इस बार कांग्रेस राज्य में पुनः सत्ता पर काबिज होगी। हम लोग पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएंगे और अधिक मनोबल के साथ आगामी 5 सालों के लिए आपकी सेवा में जुट जायेंगे।

अशोक गहलोत से मनभेद व मतभेत के सवाल पर पायलट ने कहा कि, यह वक्त पीछे लौटने का नहीं है हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और भाजपा द्वारा जो भ्रातियां फैलाई जा रही हैं उनका जवाब 3 दिसम्बर को तय हो जायेगा।

पायलट द्वारा नामांकन दर्ज कराते समय पुष्कर प्रत्याशी नसीम अख्तर इंसाफ, मसूदा विधायक राकेश पारीक, प्रशान्त बैरवा, हरीश मीणा, रघु शर्मा, टोंक प्रभारी अनिल चौपड़ा व महेन्द्र खेडी साथ आए। इसके अलावा सउद सईदी, जमील सईदी, हंसराज फागणा, धर्मेन्द्र सालोदिया, अब्दुल खालिक, शाहजेब खान, अरशद चिश्ती, जावेद चिश्ती, रामलाल सण्डिला, जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, कमलेश चावला, हंसराज गाता, दिनेश चौरसिया, अमित फारूकी, भारत वर्मा, शैलेष गुर्जर, इन्जियाज, एडवोकेट महावीर तोबडा, एडवोकेट चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव भी पायलट के साथ थे।

जिले भर से गुर्जर समाज की भारी उपस्थिति इस नामांकन रैली में दिखाई दी। नामांकन रैली में पायलट के चहेते समर्थक अकबर खान ने सचिन पायलट को 151 किलो की माला पहनाई। रैली के साथ-साथ सैकड़ों की संख्या में नाचते गाते लोग चल रहे थे और उपस्थित भीड़ के मद्देनज़र रैली में पुलिस प्रशासन चाकचोबन्द दिखा। कहा जा रहा है कि, सचिन पायलट ने नामांकन दाखिल करते हुए अपने हलफनामे में अपनी पत्नी सारा से तलाक की बात भी लिखी है।

मोदी बांग्लादेश में तैयार तीन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की मदद से विकसित की गयी तीन संयुक्त परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

यहां प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि इन परियोजनाओं में अखौरा-अगरतला क्रॉस-बॉर्डर रेल लिंक, खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट-दो परियोजना शामिल है। दोनों प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में कल पूर्वाह्न 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे।

विज्ञिप्त में कहा गया है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा और बिजली आपूर्ति बढ़ेगी। अखौरा-अगरतला रेल लिंक 12.24 किमी की दोहरी गेज लाइन परियोजना है। इसके लिए भारत ने बंगलादेश को 392.52 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दी है। इसका 6.78 किमी हिस्सा बंगलादेश और 5.46 किमी हिस्सा भारत के त्रिपुरा में है।

चुनाव आयोग ने एग्ज़िट पोल के प्रसारण पर रोक लगाई

चुनाव आयोग ने सात नवम्बर से 30 नवम्बर के लिए यह आदेश जारी किया

- **चुनाव आयोग ने कहा है कि, इन चुनाव के संबंध में मतदान के समाप्त होने के पहले 48 घंटों के दौरान किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनमत सर्वे रिपोर्ट भी प्रसारित नहीं की जा सकती है।**

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर (वार्ता)। निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए इनके संबंध में मतदान समाप्त होने तक एग्जिट पोल प्रसारण करने पर मंगलवार को रोक लगा दी।

मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभाओं के चुनाव तथा नागालैंड में तापी (सुरक्षित) सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के संबंध में यह रोक सात नवंबर पूर्वाह्न सात बजे से 30 नवंबर शाम साढ़े छह बजे तक प्रभावी होगा।

आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के मद्देनजर सात नंबर को पूर्वाह्न सात बजे से 30 नवंबर शाम साढ़े छह बजे की अवधि के बीच किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल रोक लगा रहा है। आयोग ने कहा है कि इन चुनाव के संबंध में मतदान के समाप्त होने के पहले 48 घंटों के दौरान किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनमत सर्वे रिपोर्ट भी प्रसारित नहीं की जा सकती है।

फिलिस्तीन से दस लाख लोगों को खदेड़ चुका है इज़राइल

गाजा, 31 अक्टूबर (वार्ता)। फिलिस्तीनी और इजरायल संघर्ष के बढ़ने के बीच उत्तरी गाजा पट्टी से आठ लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को निकाला गया है। इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) के प्रवक्ता जोनाथन कॉनरिकस ने मंगलवार को इस आशय का दावा किया। उन्होंने एक्स पर प्रकाशित एक वीडियो संबोधन में कहा, यह देखकर खुशी हुई कि आठ लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा पट्टी से यानी मुख्य युद्ध क्षेत्र से निकाला गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल गाजा पट्टी के दक्षिण में मानवीय सहायता पहुंचाने की सुविधा के लिए प्रयास तेज करेगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को कहा कि लड़ाई शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में 14 लाख से अधिक नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा है।

- **संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि, लड़ाई शुरू होने के बाद से गाज़ा पट्टी में 14 लाख से अधिक नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा है**

कश्मीर में 48 घंटों में आतंकियों ने तीन लोगों की हत्या की

- **हैड कांस्टेबल को आतंकियों ने गोली मारी और फरार हो गये। उल्लेखनीय है कि, सोमवार को कश्मीर में उत्तर प्रदेश के एक मजदूर और एक पुलिस इंस्पैक्टर की हत्या कर दी थी।**

श्रीनगर, 31 अक्टूबर (वार्ता)। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में मंगलवार को आतंकवादियों ने राज्य पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी।

पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों ने बारामूला जिले के वेलू क्रालपोरा निवासी हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार पर गोलीबारी की। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, गंभीर हालत में उसे उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, घायल पुलिस कर्मी ने दम तोड़ दिया और शहादत प्राप्त कर ली। हम शहीद को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस महत्वपूर्ण समय में उनके परिवार के साथ खड़े हैं।

घटना के तुरंत बाद वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी इलाके में पहुंचे और हमलावरों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में यह तीसरा लक्षित आतंकवादी हमला है।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को इस साल कश्मीर में उत्तर प्रदेश के एक मजदूर मुकेश कुमार की पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी एवं रविवार को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक आतंकवादी द्वारा क्रिकेट खेलने के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद को गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

चीन के अंतरिक्ष यात्रियों का दल पांच महीने स्पेस में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटा

- **चीन के तीन अंतरिक्ष यात्रियों ने 54 दिनों तक स्पेस में रहकर, कुल 70 अंतरिक्ष प्रयोगों को पूरा किया**
- **चीन ने 30 मई, 2023 को मानवयुक्त अंतरिक्ष यान शेनझोउ-16 लॉन्च किया था। यह चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के अनुप्रयोग और विकास का पहला चालक दल अभियान था।**

बीजिंग, 31 अक्टूबर (वार्ता)। शेनझोउ-16 का दल पांच महीने के अंतरिक्ष स्टेशन मिशन को पूरा करने के बाद मंगलवार को सुरक्षित पृथ्वी पर पहुंचा। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी (सीएमएसए) ने कहा कि अंतरिक्ष यात्री जिंग हाइपेंग, झू यांगझू और गुई हैचाओ को लेकर शेनझोउ-16 उत्तरी चीन के मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में स्थानीय समयानुसार सुबह 8:11 बजे पहुंचा। इस दल में तीन चीनी अंतरिक्ष यात्री शामिल थे।

सीएमएसए ने कहा कि शेनझोउ-16 के अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह से स्वस्थ हैं और शेनझोउ-16 का मानवयुक्त मिशन सफल हुआ और साथ ही चीन में वर्तमान में उपलब्ध सभी अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यान पायलट, स्पेसफ्लाइट इंजीनियर और पेलोड विशेषज्ञ ने अपने उड़ान और व्यावहारिक परीक्षण को पूरा कर लिया है।

सीएमएसए ने कहा कि इस अभियान ने चालक दल के अंतरिक्ष यान कार्यक्रम और अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोग करने के बाद विकास और निर्माण में एक अच्छी नींव तैयार की है।

अंतरिक्ष में चीन के पहले अंतरिक्ष यान इंजीनियर झू ने कहा कि उन्होंने विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया और पांच महीने के अभियान के दौरान देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला, अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग को देखा। चीन का अंतरिक्ष स्टेशन अद्भुत है और हमेशा देखने लायक है।

चीन ने 30 मई, 2023 को मानवयुक्त अंतरिक्ष यान शेनझोउ-16 लॉन्च किया था। यह चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के अनुप्रयोग और विकास का पहला चालक दल अभियान था। इसके चालक दल, जो 154 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे, ने कुल 70 अंतरिक्ष प्रयोगों को पूरा किया, एक स्पेस वॉक किया, अंतरिक्ष स्टेशन से एक व्याख्यान दिया और कई अवसरों पर कार्गो के आवागमन में सहायता की।

तमिलनाडू सरकार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फाइलें, नियुक्ति आदेश, भर्ती के आदेश, भ्रष्टाचार में लिप्त विधायकों और सांसदों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति तथा तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है, "राज्य सरकार द्वारा भेजी गई फाइलों, सरकारी आदेशों और नीतियों पर हस्ताक्षर न करना गैर-संवैधानिक, गैर-कानूनी, स्वैच्छाचारी, तर्कहीन तथा बदनीयती से सत्ता का दुरुपयोग है।"

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगे हैं कि विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास संविधान की धारा 200 के तहत स्वीकृति के लिए भेजे गए विधेयकों पर उनके निर्णय की समय सीमा तय होनी चाहिए। याचिका में मांग की गई है कि राज्यपाल कार्यालय में लंबित विधेयकों, सरकारी आदेशों और फाइलों का निष्पादन एक तय समय सीमा में होना चाहिए।

वकील सबरीश सुब्रमण्यम के माध्यम से दायर की गई याचिका में कहा गया है, "राज्य के राज्यपाल ने खुद को वैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार का राजनैतिक प्रतिद्वंदी बना लिया है। वे विधेयकों को बिना कारण लंबे समय तक अटकाए रखते हैं और विधानसभा के काम में अवरोध डालते हैं।"

इसमें आगे कहा गया है कि जनसेवकों के भ्रष्टाचार और अनैतिक कृत्यों के खिलाफ जांच एवं अभियोजन की स्वीकृति तथा कैदियों की समय पूर्व रिहाई जैसे मामलों में राज्यपाल असफल सिद्ध हुए है।

तमिलनाडु सरकार की याचिका में कहा गया है, "राज्यपाल की अकर्मण्यता के कारण राज्य के संवैधानिक प्रमुख तथा चुनी हुई सरकार के बीच संवैधानिक अवरोध उत्पन्न हो गया है। अपने संवैधानिक दायित्व पूरा न कर माननीय राज्यपाल जनादेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं।"

संविधान की धारा 200 के तहत जब कोई विधेयक राज्य विधानसभा में पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो उनके समक्ष चार विकल्प हैं- (1) विधेयक को स्वीकृति देना, (2) स्वीकृति रोक लेना, (3) विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना और (4) विधेयक पुनर्विचार के लिए विधायिका को लौटा देना।

सड़क दुर्घटनाओं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें सड़क दुर्घटना के विभिन्न पहलुओं, उनके कारण, स्थान व सड़क का इस्तेमाल करने वाले विभिन्न वर्गों पर इनके प्रभाव की जानकारी दी गई है।

'सरकार में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

"सरकार द्वारा प्रायोजित हमलावर" उनके आई फोन मोबाइल्स को निशाना बना रहे हैं जो ऐसा "डायनामाइट" है जिससे सरकार उड़ जानी चाहिए लेकिन कुछ नहीं हुआ।

यहां ए.आई.सी.सी. मुख्यालय पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बताया, साथ ही उन्होंने वे उद्योगपति गौतम अडानी के एकाधिकार के खतरे की बात भी की और कहा कि आज भारत में नंबर 1 प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि अडानी हैं और मोदी केवल उनके मातहत काम कर रहे है। उन्होंने कहा, "हम समझते थे कि प्रधानमंत्री नंबर 1 और गृहमंत्री अमित शाह नंबर 2 हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अडानी नंबर 1 हैं, मोदी नंबर 2 और अमित शाह नंबर 3 है।

राहुल ने कहा कि पहले एकाधिकार केवल व्यापार में होता था लेकिन आज सी.बी.आई., ई.डी., हवाई अड्डे रेलवे आदि सभी में है, इन सबका नियंत्रण अडानी के पास है। लाखों रुपए और युवाओं के रोजगार लूटे गए हैं।

'इलैक्टोरल बॉण्ड राजनैतिक दलों, खासकर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतिगामी कदम है।

भूषण ने आगे कहा कि "सत्तारूढ़ पार्टियों द्वारा ये बॉण्ड्स रिश्वत के जरिए दिए जा रहे हैं और इनसे मिलने वाली राशि का 50 प्रतिशत से अधिक केन्द्र में सत्तासीन पार्टी द्वारा ही प्राप्त किया जा रहा है।" इससे सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच समानता की भावना का उल्लंघन होता है।"

इस बीच, चुनाव आयोग की तरफ से प्रस्तुत एक एडवोकेट ने कहा कि, आयोग को सिर्फ वर्ष 2019 में ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से डोनेशन्स के बंद लिफाफे प्राप्त हुए, जबकि कोर्ट ने उन्हें बताया कि अंतरिम आदेश सभी वर्षों पर लागू होता है।

अटॉर्नी जनरल ने सोमवार को एक लिखित शपथ पत्र में कहा था कि यदि फण्ड्स को सार्वजनिक करने की मांग स्वीकार हो जाती है तो दानदाताओं की पहचान उजागर हो जाएगी।

भूषण ने कोर्ट को बताया कि "चंदे की 50 प्रतिशत से अधिक राशि केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी को मिली और शेष राशि राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी को मिली, लेकिन सत्ता से बाहर रह रहीं विपक्षी पार्टियों को एक प्रतिशत राशि भी नहीं मिली।

उन्होंने कहा कि तकरीबन सभी बॉण्ड्स कम्पनियों द्वारा खरीदे गए और उनमें से 95 प्रतिशत से ज्यादा 1 लाख करोड़ या अधिक के थे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि, केन्द्र सरकार ने इस स्कीम के जरिए कॉरपोरेट डोनेशन्स की सीमा हटाने के लिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रैग्यूलेशन एक्ट (एफ.सी.आर.ए.) में संशोधन किया।

भूषण ने कहा कि, यह प्रमाणित करने के परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं कि, सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टियां इलैक्टोरल बॉण्ड्स के जरिए कम्पनियों से रिश्वत ले रही हैं।

राजनीतिक दलों से प्राप्त इलैक्टोरल बॉण्ड्स की पक्षपाती ऑडिट रिपोर्ट्स का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि, यह आश्चर्यजनक है कि, इस स्कीम के माध्यम से रिश्वत को न्यायोचित ठहराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि, भाजपा द्वारा घोषित कुल प्राप्त अंशदान अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा घोषित कुल अंशदान का तीन गुना है।

मंगलवार को एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, वेदान्ता द्वारा इलैक्टोरल बॉण्ड्स को दिया जाने वाला चंदा बढ़ गया है, जबकि ऐसी कई खबरें आ चुकी हैं कि, कम्पनी वित्तीय संकट से गुज़र रही है।

सरकार द्वारा चालू की गई इलैक्टोरल बॉण्ड स्कीम को चुनौती देने वाली, एसोसिएशन फॉर डैमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की पी.आई.एल. के लिए अदालत में उपस्थित प्रशांत भूषण ने बिज़नैस स्टैण्डर्ड की एक न्यूज़ रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए कहा कि, इस मल्टीनैशनल माइनिंग कम्पनी ने पिछले पांच वर्षों में इलैक्टोरल बॉण्ड्स के माध्यम से राजनीतिक दलों को 457 करोड़ रूपए का चंदा दिया है। न्यूज़ में यह भी बताया गया है कि, वित्तीय वर्ष 2023 में वेदान्ता ने 155 करोड़ रू. चंदा दिया जो कि, वित्तीय वर्ष 2022 के 124 करोड़ रूपए से ज्यादा था।

प्रशांत भूषण कोर्ट से कहा कि, वित्तीय वर्ष 2023 में, वेदान्ता लिमिटेड को विभिन्न माइनिंग लाइसैंसों के लिए वरीयता प्राप्त बोली लगाने वाला घोषित किया गया। इनमें गोवा के बिचोलिम आयरन ओर ब्लॉक्स, ओडीशा के सिजमीमाली बॉक्साइड और गढ़ाचिरोली कोल ब्लॉक्स तथा छत्तीसगढ़ के केलवार डाबरी शामिल हैं।

यू.के. की वेदान्ता रिसोर्सेज़ (वी.आर.एल.), जो वेदान्ता की मूल कम्पनी है, पिछले दिनों 4.2 बिलियन डॉलर की देनदारी के कारण खबरों में थी। तथापि, कम्पनी ने अपने ऋण का 2 बिलियन डॉलर चुका दिया है और बाकी बचा पैसा 21 जनवरी 2024 तक चुकाना है।

उन्होंने आगे कहा कि, इन्वैस्टिगेटिव पत्रकारों के ग्लोबल नैटवर्थ, ऑर्गनाइज़्ड क्राइम एण्ड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजैक्ट की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि, वेदान्ता और केन्द्र सरकार के बीच बैकरूम लॉबीइंग हुई है। रिपोर्ट का टाइटल था, "इनसाइड इण्डियन एनर्जी एण्ड माइनिंग जायेंट वेदान्ताज़ कैम्पेन टु वीकन की एनवायरमैटल रैगुलेशन्स।"

बहस के दौरान भूषण ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि, इस बात के "सर्कम्स्टैंशियल एविडैन्स" है कि, इलैक्टोरल बॉण्ड स्कीम से किक बैक्स उपजे हैं।

उन्होंने अदालत में कहा कि, इस बात को साबित करने के सर्कम्स्टैंन्शियल एविडैन्स हैं कि, इलैक्टोरल बॉण्ड के माध्यम से कार्पोरेशन्स राजनीतिक दलों को किक बैक्स देते हैं।

चन्द्रबाबू नायडू...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजनैतिक जीत समझ रहे है जबकि सभी जानते है कि यह केवल स्वास्थ्य के कारणों से मिली है। टी.डी.पी. के राज्य अध्यक्ष किंजारापू अट्चन नायडू ने कहा, "जगन (मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी) का पतन तभी आरंभ हो जाएगा जब हमारे नेता चंद्रबाबू जेल से बाहर कदम रखेंगे। उन्होंने कहा कि नायडू सभी गैर कानूनी मुकदमों से बरी हो जाएंगे।

भाजपा की प्रदेश प्रमुख डी. पुरंदरेश्वरी ने भी नायडू को अंतरिम जमानत दिए जाने का स्वागत किया और कहा कि, मैंने पहले भी गिरफ्तारी के तरीके का विरोध किया था। पुरंदरेश्वरी तेलुगुदेशम के संस्थापक व आंध्र के मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की पुत्री हैं। पुरंदरेश्वरी और चन्द्रबाबू नायडू की पत्नी सगी बहने हैं।

नायडू के पुत्र एन. लोकेश ने अंतरिम जमानत मिलने का स्वागत किया एवम् कहा कि, उसे भारी राहत मिली है कि उसके पिता अपने विश्वस्त चिकित्सकों की देखरेख में रहेंगे। उसने पूर्व में आरोप लगाया था कि उसके पिता की जान खतरे में है अगर उन्हें कुछ हुआ तो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जिम्मेवार होंगे।

लोकेश ने एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा कि, सी.बी.एन (चन्द्रबाबू नायडू) की लाइफ को खतरा है। उन्हें जानबूझ कर आहत किया जा रहा है। उनका सुरक्षा खतरे में है। मच्छरों के बीच रहने को मजबूर सी.बी.एन. को प्रदूषित पानी दिया जा रहा है। उनका वजन गिर रहा है उन्हें कई प्रकार के संक्रमण व एलर्जी है, उन्हें मैडिकल हैल्थ भी नहीं दी जा रही है।

समूची पार्टी और नायडू के परिजन व सड़कों पर उतर आए हैं। नायडू की पत्नी एन. भुवनेश्वरी ने आंध्र प्रदेश का दौरा शुरू कर दिया ताकि वे जेल में बंद अपने पति के लिए सहानुभूति जुटा सके। इसी के साथ वे पार्टी को भी चुनाव के लिए तैयार कर रही है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908